[2017] 2 एस.सी.आर. 466

एस कृष्णा श्रद्धा

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या 1081/2017)

19 जनवरी 2017

[दीपक मिश्रा और आर. एफ. नरीमन, जेजे.]

शिक्षा:

प्रवेश- एमबीबीएस पाठ्यक्रम- गलत तरीके से प्रवेश से वंचित करना- कला के साथ संवैधानिक न्यायालयों का कर्तव्य अर्न्तगत अनुच्छेद 32, 136 और 226- जैस्मीन कौर के मामले में निर्णय पर पुनर्विचार, जिसमें निर्धारित समय- सीमा समाप्त होने के बाद प्रवेश न मिलने पर एकमात्र उपाय के रूप में मौद्रिक मुआवजा देना शामिल था, जब ऐसी चूक परामर्श/प्रशासन प्राधिकारी द्वारा किए गए दोषों का परिणाम थी- माना गया: मेधावी छात्रों को संस्थान या इससे जुड़े व्यक्तियों की किसी गलती के कारण प्रवेश पाने में किसी बाधा का सामना नहीं करना चाहिए- उनके पास शिकायतों के निवारण के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। यह एक शिकायत है कि मौलिक अधिकार से संबंधित है जब इस प्रकृति का कोई मामला संवैधानिक अदालत में आता है, तो यह अदालत का कर्तव्य बन जाता है कि वह यह पता करे कि क्या प्राधिकारी ने उसे प्रदत्त शक्तियों के भीतर कार्य किया था या उसी से विचलित हुआ था जिसके परिणामस्वरूप अन्याय हुआ था। पीड़ित व्यक्ति

के लिए- मौलिक अधिकार के निवारण को केवल मुआवजा देने के संदर्भ में नहीं तौला जा सकता है- मुआवजा देना एक अतिरिक्त राहत हो सकता है गलत तरीके से प्रवेश से वंचित करने के लिए मुआवजा पर्याप्त या एकमात्र उपाय नहीं हो सकता है, क्योंकि यह शैक्षणिक कैरियर को प्रभावित करता है एक छात्र का- जैस्मीन कौर के मामले में निर्णय पर एक बड़ी बेंच- मैक्सिम द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है- "लेक्स नॉन इंटेंडिट एलिक्विड असंभव- सिद्धान्त/सिद्धान्तों- पुर्नस्थापना का सिद्धान्त।

प्रवेश- एमबीबीएस पाठ्यक्रम- अपीलकर्ता ने चयनित उम्मीदवारों की तुलना में अधिक मेधावी होने के बावजूद खेल कोटा में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश से इनकार कर दिया- उच्च न्यायालय ने जैस्मीन कौर के मामले पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ता को प्रवेश का लाभ देने से इनकार कर दिया और इस आधार पर मुआवजा दिया कि प्रवेश के लिए कट- ऑफ तिथि समाप्त हो गई थी। हालाँकि, यह मानते हुए कि अपीलकर्ता पाने का हकदार था। प्राथमिकता और इसमें शामिल विभिन्न अधिकारियों की ओर से खामियां थीं। अभिनिर्धारित: अपीलकर्ता- छात्र ने अन्तर्गत अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटाया काफी तत्परता से और उसकी ओर से कोई देरी नहीं हुई और प्रवेश की प्रक्रिया के लिए बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने में अपीलकर्ता को निर्देशित किया गया- भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 और 21

मामले को उचित बड़ी बेंच न्यायालय के समक्ष रखे जाने का उल्लेख करते हुए अभिनिर्धारित किया:-

1. जैस्मीन कौर का मामला प्रवेश की राहत देने पर रोक लगाता है, यदि यह निर्धारित समय- सीमा के भीतर है, और फिर सीटें भर जाती हैं और सी प्रवेश देने की गुंजाइश समय- सारिणी के ग्रहण के कारण समाप्त हो जाती है, तो यह निर्धारित करता

है, तो ऐसी परिस्थितियों में, उम्मीदवार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उचित मुआवजा ही दिया जा सकता है। (पैरा 22] [485- सी- डी]

चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य बनाम जैस्मीन कौर और अन्य (2014) 10 एससीसी 521: [2014] 9 एससीआर 1122- अभिनिर्धारित, पुनर्विचार की आवश्यकता है।

2.1. इस न्यायालय ने प्रवेश के मामलों में हमेशा योग्यता पर जोर दिया है क्योंकि मेधावी छात्रों को संस्थान या उससे जुड़े व्यक्तियों की किसी गलती के कारण प्रवेश पाने में किसी बाधा का सामना नहीं करना चाहिए। उसके पास अपनी शिकायतों के निवारण के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। यह एक शिकायत है जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। किसी व्यक्ति को कानून के शासन द्वारा अधिकार प्रदान किया जाता है और यदि वह कानून का शासन स्थापित करने की प्रक्रिया के माध्यम से उपचार चाहता है और उसे इससे वंचित कर दिया जाता है, तो यह कभी भी वास्तविक न्याय के उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा। जब इस प्रकृति का कोई मामला संवैधानिक अदालत में आता है, तो यह अदालत का कर्तव्य बन जाता है कि वह यह पता लगाए कि क्या प्राधिकारी ने उसे प्रदत्त शक्तियों के भीतर कार्य किया था या उससे भटक गया था, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है। मौलिक अधिकार के निवारण को केवल मुआवजा देने के संदर्भ में नहीं तौला जा सकता। (पैरा 26] [487- सी- एफ]

2.2 मुआवजा देना एक अतिरिक्त राहत हो सकती है। इसे एकमात्र उपाय के रूप में मुआवजा देने तक ही सीमित रखने से उन मौलिक अधिकारों का मूल उद्देश्य विफल हो जाएगा, जिन्हें संविधान ने प्रदत्त किया है, ताकि उक्त अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अधिकार को मान्यता देना, यह निष्कर्ष दर्ज करना कि अधिकार

का उल्लंघन हुआ है और अपेक्षित राहत से इनकार करना अनुचित होगा। एक युवा छात्र को यह महसूस नहीं करना चाहिए कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने का उसका पूरा प्रयास कुछ अधिकारियों की गलती या नाटकीय डिजाइन के कारण निरर्थक हो जाता है और वे मुआवजे के रूप में कुछ राशि देकर बच सकते हैं। यह न केवल पीड़ादायक हो सकता है, बल्कि अधिकारियों की लापरवाही या बुरी योजना या लाइलाज लालच के कारण प्रीमियम देना भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में, न्याय बहुत दूर हो सकता है और संवैधानिक न्यायालय के दरवाजे खटखटाना एक व्यर्थ प्रयास हो सकता है। यह सर्वविदित है कि कानून का इरादा कुछ भी असंभव नहीं है; "लेक्स नॉन इंटेंडिट एलिक्विड इम्पॉसिबल"। लेकिन जब यह संभावना के दायरे में हो और राहत से इनकार करने से "न्याय की महिमा" को ठेस पहुंचती है, इसे नकारा नहीं जाना चाहिए। इसके विपरीत, राहत देने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। [पैरा 26] [487- एफ- एच: 488- ए- बी]

आशा बनाम पं. बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं अन्य (2012) 7 एससीसी 389: [2012] 6 एससीआर 876; हर्षाली पुत्री सुदामराव वानखेड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2005) 13 एससीसी 464 पर भरोसा किया गया।

2.3 हालाँकि, ऐसे मामले हैं जहां इस न्यायालय ने मुआवजा दिया था क्योंकि कोई अन्य विकल्प नहीं था और मोचन का एकमात्र तरीका मुआवजा देना था। यह बताना जरूरी है कि कानूनी रूप से देय राहत देना अदालत का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। जहां पुनर्स्थापन का सिद्धांत लागू किया जा सकता है और ऐसी कोई असंभवता नहीं है कि इसे अस्वीकार करना न्याय के लिए अभिशाप होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि एक अवधारणा के रूप में पुनर्स्थापन की सराहना की जाती है, जैसा कि परंपरागत रूप से समझा जाता है, एक पीड़ित पक्ष की गलत काम करने से पहले की स्थिति में बहाली

है। इसे केवल मौद्रिक परिमाणीकरण तक ही सीमित किया जा सकता है यदि उल्लंघन का समाधान करने में सक्षम नहीं है। ऐसा होने पर, गलत तरीके से प्रवेश से वंचित करने के लिए मुआवजा पर्याप्त या एकमात्र उपाय नहीं हो सकता है, क्योंकि यह किसी छात्र के शैक्षणिक करियर को प्रभावित करता है। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां क्षतिपूर्ति बहुत कठोर हो सकती है। [पैरा 27] [488- डी- एफ]

2.4 उपरोक्त के दृष्टिगत जैस्मीन कौर का निर्णय मामले पर एक बड़ी बेंच द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है। [पैरा 31] [490- सी- डी]

अनीश डी. लवंडे और अन्य बनाम गोवा राज्य और अन्य (2014) 1 एससीसी 554: [2013] 17 एससीआर 55 की व्याख्या।

स्टेट बनाम फ़ॉकनर वाल्टर क्लार्क, अमेरिकी न्यायविद, 1921: एमबीबीएस/बीडीएस चयन बोर्ड बनाम चंदन मिश्रा (1995) पूरक 3 एससीसी 77, चंदन मिश्रा बनाम एमबीबीएस/बीडीएस चयन बोर्ड (1994) 77 कट एलटी 624; विभाग सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, यूटी चंडीगढ़ बनाम कुलदीप सिंह (1997) 9 एससीसी 199: [1997] 1 एससीआर 454; जूलियस बनाम ऑक्सफोर्ड के लॉर्ड बिशप (1880) 5 एसी 214, कॉमरेड पुलिस बनाम गोरधनदास भानजी एआईआर 1952 एससी 16: [1952] एससीआर 135; के.एस. भोईर बनाम महाराष्ट्र राज्य (2001) 10 एससीसी 264: [2001] 5 पूरक एससीआर 593, फैज़ा चौधरी बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य (2012) 10 एससीसी- 149: [2012] 7 एससीआर 528; सत्यब्रत साहू बनाम उड़ीसा राज्य (2012) 8 एससीसी 203: [2012] 10 एससीआर 204; भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम कर्नाटक राज्य (1998) 6 एससीसी 131: [1998] 3 एससीआर 740; प्रिया गुप्ता बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2012) 7 एससीसी 433: [2012] 5 एससीआर 768; क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बनाम पंजाब राज्य (2010) 12 एससीसी 167; बिहार

राज्य बनाम संजय कुमार सिन्हा (1990) 4 एससीसी 624: [1989] 2 पूरक एससीआर 168; मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम मधु सिंह (2002) 7 एससीसी 258: [2002] 2 पूरक एससीआर 228; जीएसएफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल एसो. बनाम एसो स्व- वित्तपोषण तकनीकी संस्थान (2003) 12 एससीसी 414; द्वारका नाथ बनाम आईटीओ एआईआर 1966 एससी 81: [1965] एससीआर 536; पंजाब राज्य सलिल सभलोक (2003) 5 एससीसी 1: [2003] 1 एससीआर 877; एस. निहार अहमद बनाम डीन वेलाम्मल मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अनुसंधान संस्थान और अन्य (2016) 1 एससीसी 662 [2015] 10 एससीआर 242; पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ अपने प्रिंसिपल बनाम संजय गुलाटी और अन्य के माध्यम से। (1983) 3 एससीसी 517: [1983] 2 एससीआर 801; रुदुल शाह बनाम बिहार राज्य (1983) 4 एससीसी 141: [1983] 3 एससीआर 508; सेबेस्टियन होंग्रे बनाम भारत संघ एआईआर 1984 एससी 571: [1984] 1 एससीआर 904, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड बनाम चंद्रिमा दास (2000) 2 एससीसी 465: [2000] 1 एससीआर 480; जंग सिंह बनाम बृज लाल एवं अन्य एआईआर 1966 एससी 1631: [1964] एससीआर 145 का उल्लेख किया गया है।

केस कानून संदर्भ

[2014] 9 एससीआर 1122	अभिनिर्धारित, पुनर्विचार की आवश्यकता है	पैरा 2, 31
[2013] 17 एससीआर 55	व्याख्या की	पैरा 19
(1995) पूरक 3 एससीसी 77	संदर्भित	पैरा 15
[1997] 1 एससीआर 454	संदर्भित	पैरा 15
[1952] एससीआर 135	संदर्भित	पैरा 15
[2001] 5 पूरक एससीआर 593	संदर्भित	पैरा 17

[2012] 7 एससीआर 528	संदर्भित	पैरा 17
[2012] 10 एससीआर 204	संदर्भित	पैरा 17
[1998] 3 एससीआर 740	संदर्भित	पैरा 17
[2012] 5 एससीआर 768	संदर्भित	पैरा 18
(2010) 12 एससीसी 167	संदर्भित	पैरा 19
[1989] 2 पूरक एससीआर 168	संदर्भित	पैरा 20
[2002] 2 पूरक एससीआर 228	संदर्भित	पैरा 20
(2003) 12 एससीसी 414	संदर्भित	पैरा 20
[1965] एससीआर 536	संदर्भित	पैरा 21
[2003] 1 एससीआर 877	संदर्भित	पैरा 21
[2015] 10 एससीआर 242	संदर्भित	पैरा 22
[1983] 2 एससीआर 801	संदर्भित	पैरा 25
[2012] 6 एससीआर 876	पर भरोसा	पैरा 26
(2005) 13 एससीसी 464	पर भरोसा	पैरा 26
[1983] 3 एससीआर 508	संदर्भित	पैरा 27
[1984] 1 एससीआर 904	संदर्भित	पैरा 27
[2000] 1 एससीआर 480	संदर्भित	पैरा 27
[1964] एससीआर 145	संदर्भित	पैरा 28

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1081/2017।

तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद उच्च न्यायालय के 2015 के डब्ल्यूपी संख्या 32710 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 25.01.2016 से।

पी.एस. नरसिम्हा, एएसजी (एसी), विकास सिंह, वरिष्ठ वकील, के., परमेश्वर, अश्वनी कुमार एन., गुंटूर प्रभाकर, सुश्री प्रेरणा सिंह, वाई. राजा गोपाल राव, वाई. विस्मई राव, सुश्री मंजीत कृपाल, पी. शादत कुमार, गौरव शर्मा, प्रतीक भाटिया, धवल मोहन, सुश्री वारा गौड़, अधिवक्ता., उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय दीपक मिश्रा, जे. सुनाया गया।

1. छुट्टी स्वीकृत।

2. विशेष अनुमति द्वारा इस अपील में विचार के लिए उभरने वाला केन्द्रापसारक मुद्दा हमें सोचने के लिए मजबूर करता है और हमें इस सिद्धांत पर विचार करने के लिए बाध्य करता है कि क्या मौद्रिक मुआवजे के अनुदान को वंचित छात्र के लिए एकमात्र और पर्याप्त उपाय माना जा सकता है। एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के बावजूद, वह मेधावी, सतर्क और मेहनती है और इस तरह जिद का रास्ता छोड़ देता है और अंततः निर्दोष पाया जाता है, उसे उस पाठ्यक्रम में प्रवेश न मिलने के लिए मजबूर किया जाता है जिसके लिए उसने आकांक्षा की थी और उसे उपयुक्त पाया था क्योंकि प्रवेश की प्रक्रिया से आंतरिक रूप से जुड़े परामर्श प्राधिकारी या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा की गई चूक, और विचार- विमर्श के लिए उठने वाला सहायक मुद्दा यह है कि क्या संवैधानिक अदालतें, चाहे वह उच्च न्यायालय हो या यह न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय संविधान या संविधान के अनुच्छेद 32 या 136 के तहत, न्यायालय द्वारा उम्मीदवार को राहत देने से इनकार करने के लिए निर्धारित समय- सारिणी की समाप्ति के कारण विकलांगता महसूस होगी, "समय समाप्त होने के कारण राहत से इनकार किया गया"। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विकास सिंह इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे कि चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य बनाम जैस्मीन कौर और अन्य (2014)

10 एससीसी 521 में दो- न्यायाधीशों की बेंच के फैसले के आधार पर मुआवजा देना ही एकमात्र संभावित उपाय है। जिस पर अपीलकर्ता को राहत देने से इनकार करने के लिए आक्षेपित निर्णय और आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किया गया है (क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था) और जो हमें "अंधविश्वासपूर्ण पवित्रता" पर विचार करने के लिए मजबूर करता है जैसा कि प्रस्तुत किया गया है राज्य बनाम फुल्कनर वाल्टर क्लार्क अमेरिकी न्यायविद 1921 में और साथ ही पुनरावृत्ति भी करते हैं ओलिवर वेंडेल होलमेस का कथन:-

> "किसी भी दायरे की कल्पना के लिए शक्ति का सबसे दूरगामी रूप पैसा नहीं है, यह विचारों का आदेश है" ओलिवर वेंडेल होम्स "द पाथ ऑफ़ द लॉ, कलेक्टेड लीगल पेपर्स 1921
>
> और सबसे ऊपर, हम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और संरक्षण के लिए संवैधानिक न्यायालयों के प्रति अपने कर्तव्य से बेखबर नहीं रह सकते हैं। "

3. विवाद को समझने के लिए जिन तथ्यों को बताया जाना आवश्यक है, वे एक संकीर्ण दायरे में हैं। अपीलकर्ता ने डब्ल्यू.पी. को प्राथमिकता दी। तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में न्यायिक उच्च न्यायालय के समक्ष 2015 की संख्या 32710 में आरोप लगाया गया कि डॉ. एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रतिवादी नंबर 2 ने प्रवेश लेने के लिए उसकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया था। खेल और खेल कोटा में शैक्षणिक सत्र 2015- 2016 के लिए प्रथम वर्ष एमबीबीएस पाठ्यक्रम और अस्वीकार्य आधारों पर प्रतिवादी संख्या 7 और 8 को प्रवेश दिया और उस आधार पर विश्वविद्यालय को इस मामले पर विचार करने के लिए परमादेश की रिट जारी करने की मांग की। खेल और खेल कोटे में दूसरों की तुलना में

प्राथमिकता, क्योंकि वह इसकी हकदार थी। हमें तथ्यों पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि न तो विश्वविद्यालय और न ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है।

4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री के. परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता खेल और खेल कोटा में उन उम्मीदवारों की तुलना में अधिक मेधावी था जिन्हें दिया गया है। उन्होंने हमारा ध्यान उच्च न्यायालय के फैसले के कुछ अंशों की ओर आकर्षित किया है। वे इस प्रकार पढ़ते हैं:-

> "11.....इस न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री से, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने 28 सितंबर से 12 अक्टूबर, 2014 तक सीनियर डिवीजन के तहत रेउस, स्पेन में आयोजित विश्व कलात्मक स्केटिंग चैम्पियनशिप, 2014 में भाग लिया और प्रमाणन प्राप्त किया इस आशय का प्रमाण किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय रोलर स्केटिंग महासंघ ने दिया है। जब रिकॉर्ड पर ऐसा प्रमाणन है, तो याचिकाकर्ता को इस आधार पर प्राथमिकता देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि तीसरे प्रतिवादी- एसएएपी ने 22.08.2015 को दूसरे प्रतिवादी- विश्वविद्यालय से दस्तावेज एकत्र करने के बाद तत्काल कदम नहीं उठाए हैं। दूसरे प्रतिवादी- विश्वविद्यालय द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में किए गए कथनों से, यह स्पष्ट है। वर्ष 2015- 2016 के लिए शैक्षणिक सत्र 01.09.2015 से शुरू हुआ और इसके अलावा, 8 वें प्रतिवादी को तीसरे

प्रतिवादी द्वारा दी गई प्राथमिकता के अनुसार दिए गए प्रवेश के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया। यह कहा गया है कि 8" प्रतिवादी ने 01.10.2015 से कक्षाओं में भाग लेना शुरू कर दिया। "

और फिर:-

"13. इसके अलावा, चंडीगढ़ प्रशासन (2 सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक वर्ष की खाली सीटों को अगले वर्ष की अनुमत सीटों के साथ टेलीस्कोपिंग नहीं किया जा सकता है, यानी सीटों को आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कोई उम्मीदवार कितना भी मेधावी हो और प्रवेश के योग्य हो। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (3 सुप्रा) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि अदालतों को इस बात पर चर्चा किए बिना निर्णयों पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि तथ्यात्मक स्थिति किस तरह से फिट बैठती है। निर्णय की तथ्यात्मक स्थिति जिस पर निर्भरता रखी गई है।

14. मौजूदा मामले में, यह स्पष्ट है कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए खेल और खेल श्रेणी के तहत आरक्षण के लिए याचिकाकर्ता के दावे के समर्थन में आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करने के बावजूद, उसे उचित प्राथमिकता और एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था, यदि विश्व चैंपियनशिप में याचिकाकर्ता की भागीदारी को सरकार द्वारा अधिसूचित मानदंडों के अनुसार माना जाता, तो वह प्राथमिकता 10 की हकदार थी, जिस स्थिति में वह एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए भी हकदार थी। इस तथ्य के बावजूद कि 22.08.2015 को तीन प्रतिवादी- एसएएपी के अधिकारियों

द्वारा प्रमाण पत्र एकत्र किए गए थे। यदि भारतीय खेल प्राधिकरण से इसकी पुष्टि की आवश्यकता थी, तो उन्होंने शीघ्रता और लगन से कार्य नहीं किया। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, पुष्टि केवल तीसरे प्रतिवादी द्वारा दी जानी है, लेकिन किसी अन्य निकाय द्वारा नहीं। जब प्रमाणपत्रों की पुष्टि के लिए तीसरे प्रतिवादी पर वैधानिक दायित्व है, तो वह केवल इस आधार पर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने दिनांक 18.09.2015 के पत्र का जवाब नहीं दिया है। विश्व चैंपियनशिप में याचिकाकर्ता की भागीदारी के संबंध में किसी भी विवाद की अनुपस्थिति में, जो कि रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित है, केवल इस आधार पर कि दिनांक 18.09.2015 को संबोधित पत्र का प्रतिवादी 3 द्वारा कोई जवाब नहीं था, याचिकाकर्ता को उचित प्राथमिकता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए था। साथ ही, 22.08.2015 को प्रमाण पत्र एकत्र करने के बाद, 3 प्रतिवादी- एसएएपी द्वारा केवल 18.09.2015 को संबंधित प्राधिकारी को संबोधित करने का कोई कारण नहीं है। प्राथमिकता सूची को अंतिम छोर यानी 28- 29.09.2015 को अग्रेषित करके, याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत रखने के अवसर से वंचित कर दिया गया। साथ ही, दूसरे प्रतिवादी- विश्वविद्यालय द्वारा दायर जवाबी हलफनामे से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2015- 16 के लिए शैक्षणिक सत्र 01.09.2015 से शुरू हुआ, खेल और खेल कोटा के तहत उम्मीदवारों ने 01.10.2015 से कक्षाओं में भाग लेना शुरू कर दिया है। ऐसे में, शैक्षणिक सत्र 2015- 2016 के लिए याचिकाकर्ता को प्रवेश देने के

लिए इस समय कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। " [जोर दिया गया]

5. उपरोक्त विश्लेषण से, यह अस्पष्ट है, किसी गहन विचार और विचार-विमर्श की आवश्यकता नहीं है जो कभी- कभी मस्तिष्क को परेशान कर सकता है, हालांकि उच्च न्यायालय एक स्पष्ट और स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलकर्ता प्राथमिकता पाने का हकदार था, फिर भी उसने इनकार कर दिया है जैस्मीन कौर के मामले में फैसले पर भरोसा करते हुए प्रवेश का लाभ दिया गया और रु. 5,00,000/- (केवल पांच लाख रुपये) का मुआवजा दिया गया। यह भी देखा गया है कि अपीलकर्ता को प्रवेश का लाभ नहीं दिया गया था, जबकि वह दूसरों की तुलना में अधिक मेधावी था, केवल इस आधार पर प्राप्त अंकों के आधार पर कि समय समाप्त हो गया था। इसलिए, प्रासंगिक प्रश्न यह उठाया जाना चाहिए कि क्या यह उस छात्र के लिए उचित या उचित है जिसने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत काफी तत्परता से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और उसकी ओर से कोई देरी या चूक नहीं हुई है और आगे जहां उसने नहीं किया है प्रवेश की प्रक्रिया के लिए बनाए गए नियमों या विनियमों के तहत निर्धारित किसी भी प्रक्रिया का पालन करने में गलती होने पर, संभवतः न्यायालय के कर्तव्य को समझते हुए मौद्रिक मुआवजा देकर उसकी शिकायत को कम किया जा सकता है और इससे आगे नहीं।

6. जब मामला पहले सूचीबद्ध किया गया था, तो हमने अपीलकर्ता- छात्र को प्रवेश की अनुमति दी थी और तदनुसार उसे प्रवेश दिया गया है। श्री विकास सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील, जिनकी सहायता श्री गौरव शर्मा कर रहे हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने काफी हद तक स्वीकार किया है कि प्रवेश में गड़बड़ी की आवश्यकता नहीं है और अपीलकर्ता को पाठ्यक्रम में भर्ती

कराया गया है पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी जा सकती है। . इसलिए, अपीलकर्ता के संबंध में कोई भी विवाद प्रवेश बंद है, और हम इस संबंध में श्री सिंह एवं श्री शर्मा की सराहना के साथ रुख को दर्ज करते हैं।

7. ऐसा कहने के बाद, सभी संभावनाओं में, हमने अपील का निपटारा कर दिया होता। लेकिन श्री पी.एस. नरसिम्हा, विद्वान वरिष्ठ वकील, जिन्हें न्यायालय की सहायता के लिए एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया गया है और श्री के. परमेश्वर, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने उनके आदेश पर पूरी विनम्रता और ईमानदारी के साथ प्रस्तुत किया कि यह एक आवर्ती समस्या है और इसके आधार पर जैस्मीन कौर (सुप्रा) में दिए गए फैसले से एक बाधा पैदा हो गई है और एक मेधावी उम्मीदवार की वास्तविक शिकायत को कम करने के लिए कृत्रिम बाधा की कल्पना की गई है, और, एक तरह से, यह संवैधानिक अदालतों की वास्तविक मूल अनुदान देने की शक्ति को खत्म कर देता है। राहत या राहत को ढालना और इसलिए, उक्त निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

8. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विकास सिंह इस आधार पर उक्त प्राधिकारी का पुरजोर समर्थन करेंगे कि इस न्यायालय द्वारा प्रवेश के लिए निर्धारित समय का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए और इसे कभी भी पटरी से उतरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, कोई परिस्थिति नहीं।

9. विद्वान न्याय मित्र श्री नरस्मिहा द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आशा बनाम पं. बी.डी. शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड अन्य (2012) 7 एससीसी 389 ने प्रवेश प्रक्रिया की प्रक्रियात्मक पवित्रता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के एक अभिन्न पहलू के रूप में मान्यता दी है और आगे फैसला सुनाया है कि

असाधारण परिस्थितियों में, 30 सितंबर की समय सीमा बाधा के रूप में कार्य नहीं करनी चाहिए। प्रवेश की पूर्ण राहत देने के लिए, यदि तीन शर्तें पूरी होती हैं। विद्वान न्यायमित्र का तर्क होगा कि एक उम्मीदवार को मेधावी होना चाहिए और न्यायालय के प्रति उसका दृष्टिकोण बेदाग होना चाहिए; कि उसे शीघ्रता से न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, और प्रवेश से इनकार परामर्श प्राधिकारी सहित संबंधित प्राधिकारियों की किसी गलती या लापरवाही के कारण हुआ होगा। उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश देते समय अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे निष्पक्षता के मानदंडों का कड़ाई से पालन करें और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे पूरी तरह से सतर्क रहें, पारदर्शिता के सिद्धांत का ईमानदारी से पालन करें और जब संवैधानिक न्यायालय को ऐसा लगे विचलन है, तो अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उनका आग्रह है कि ऐसे मामलों में मुआवजा देना मौलिक सिद्धांतों और मूल्यों के विपरीत होगा। यह संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित है और संविधान के अनुच्छेद 21 के आवश्यक पहलू को नष्ट करने की संभावना है जो जीवन के अधिकार को मान्यता देता है। जिसमें समय- समय पर इस न्यायालय द्वारा विस्तारित कई अधिकारों को शामिल किया गया है। जिसमें जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने का कानून अधिकार भी शामिल है। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार न्यायालय द्वारा उक्त विस्तार को न तो सीमित किया जाना चाहिए और न ही पंगु बनाया जाना चाहिए।

10. इस समय, हम बार में उद्धृत किए गए निर्णयों पर नजर डालना उचित समझते हैं। आशा (सुप्रा) में, न्यायालय ने कहा कि यह समय की मांग और न्याय की मांग थी कि इस न्यायालय ने अपने निर्णयों को स्पष्ट किया और सिद्धांतों को अधिक सटीकता के साथ बताया ताकि प्रक्रिया में रंगीन दुरुपयोग और शक्ति के मनमाने

प्रयोग को समाप्त किया जा सके। सभी संबंधितों द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में चयन और प्रवेश के संबंध में। कोर्ट ने चार सवाल पूछे. वे हैं:-

> "ए) क्या ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में पाठ्यक्रमों और कॉलेजों की प्राथमिकता के लिए योग्यता के नियम के सख्त पालन के सिद्धांत में कोई अपवाद है?
>
> बी) क्या प्रासंगिक शैक्षणिक वर्ष की 30 सितंबर की कट- ऑफ तारीख वह तारीख है जो किसी अपवाद को स्वीकार करती है?
>
> सी) नियमों और विनियमों के संदर्भ में प्रवेश में योग्यता, निष्पक्षता और पारदर्शिता के नियम का पालन सुनिश्चित करते हुए अदालतें क्या राहत दे सकती हैं और किस हद तक इसे ढाल सकती हैं?
>
> डी) आदेश पारित करने से पहले अदालत द्वारा किन मुद्दों से निपटने और निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है जो अधिक न्यायसंगत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इस विषय को नियंत्रित करने वाले इस अदालत के नियमों और निर्णयों के ढांचे के सख्त अनुपालन में हैं?"

11. दूसरे प्रश्न पर विचार करते समय न्यायालय ने इस प्रकार कहा:-

> "30. इसमें कोई संदेह नहीं है कि 30 सितंबर कट- ऑफ तिथि है। अधिकारी विशेष रूप से निर्धारित कट- ऑफ तिथि से आगे प्रवेश नहीं दे सकते हैं। लेकिन जहां उम्मीदवार की कोई गलती नहीं है और उसे मनमाने कारणों से प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है, क्या कट- ऑफ तारीख को ऐसे छात्रों के प्रवेश में बाधा के रूप में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए, खासकर तब जब इसके परिणामस्वरूप

मेधावी उम्मीदवार का पेशेवर करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, यह वह सवाल है जिसका हमें जवाब देना होगा। "

12. इतना कहने के बाद, न्यायालय ने निष्कर्ष दर्ज करना शुरू कर दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन स्पष्ट रूप से अनुचित था कि अपीलकर्ता को प्रवेश से वंचित कर दिया गया। इसके बाद, यह इस प्रकार कहा गया:-

"32. हालांकि ऐसे दुर्लभतम मामले या असाधारण परिस्थितियां हो सकती हैं जहां अदालतों को राहत देनी पड़ सकती है और 30 सितंबर की कट- ऑफ तारीख को अपवाद बनाना पड़ सकता है, लेकिन उन मामलों में, अदालत को पहले एक निष्कर्ष देना होगा कि कोई नहीं गलती उम्मीदवार की है, उम्मीदवार ने बिना किसी देरी के अपने अधिकारों और कानूनी उपायों का तेजी से पालन किया है और अधिकारियों की ओर से गलती हुई है और चयन और प्रवेश देने की प्रक्रिया में कुछ नियमों, विनियमों और सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। जहां प्रवेश से इनकार उम्मीदवार के समानता और समान व्यवहार के अधिकार का उल्लंघन करता है, वहां उम्मीदवार को ऐसी असाधारण राहत से इनकार करना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और अनुचित होगा। [आरती सप्रू बनाम जम्मू- कश्मीर राज्य देखें [(1981) 2 एससीसी 484]; छवि मेहरोत्रा बनाम महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं [(1994) 2 एससीसी 370]; और अरविंद कुमार कनकने बनाम यूपी राज्य [(2001) 8 एससीसी 355]"

13. न्यायालय ने कहा कि भले ही शर्तें पूरी हो जाएं, फिर भी न्यायालय को यह तय करने के लिए बुलाया जाएगा कि राहत दी जानी चाहिए या नहीं, और यदि दी

जाती है, तो मुआवजे के साथ या बिना मुआवजे के दी जानी चाहिए। इसके बाद, न्यायालय ने कुछ तथ्यों पर ध्यान दिया और निम्नलिखित तरीके से राहत दी:-

> "37. उपरोक्त आंकड़ों से, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता नियमों के अनुसार अपने बीडीएस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने में बुरी तरह विफल रही है और इस प्रकार, उसने एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए पूर्व-आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं किया है, यह मानते हुए कि बीडीएस और एमबीबीएस पाठ्यक्रम पहले छह महीनों के लिए समान हैं। इन परिस्थितियों में और यह पाते हुए कि अपीलकर्ता इस सीमित सीमा तक गलती पर है, हमारा विचार है कि वर्तमान अपील में अपीलकर्ता को दी जाने वाली एकमात्र राहत उत्तरदाताओं को एक निर्देश है अपीलकर्ता को शैक्षणिक वर्ष 2011- 12 में नहीं बल्कि वर्तमान शैक्षणिक वर्ष यानी 2012- 2013 में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दें, वह भी इस शर्त के अधीन कि वह बिना किसी लाभ के शुरू से ही अपना एमबीबीएस पाठ्यक्रम जारी रखेगी। बीडीएस में उसका पाठ्यक्रम। यदि इस बीच कोई परीक्षा आयोजित की गई है, तो यह माना जाएगा कि वह उनमें शामिल नहीं हुई थी। सभी इरादों और प्रयोजनों के लिए परीक्षाएं और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। उसे एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश देते समय, अधिमानतः और यदि यह अनुमेय है, तो एमबीबीएस पाठ्यक्रम में किसी भी अन्य उम्मीदवार के प्रवेश में बाधा न डाली जाए। यदि किसी भी कारण से, ऐसा करना संभव नहीं है, तो उस स्थिति में, मेरिट में अंतिम स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार, जिसे एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है, को बीडीएस पाठ्यक्रम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और

अपीलकर्ता को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा। हम यह भी निर्देश देते हैं कि ऐसे उम्मीदवार को अपना बीडीएस पाठ्यक्रम शुरू से शुरू करने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि उम्मीदवार ने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की उपस्थिति आवश्यकताओं को पूरा किया हो।

XXX XXX XXX

41. उपरोक्त दर्ज किए गए कारणों और ऊपर उल्लिखित निर्देशों के साथ, हम उत्तरदाताओं को निर्देश देते हैं कि वे अपीलकर्ता को चालू शैक्षणिक वर्ष में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दें, बशर्ते कि वह शुरुआत से ही अपना एमबीबीएस पाठ्यक्रम ऊपर बताई गई शर्तों के अनुसार जारी रखेगी और हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, हम कोई लागत नहीं देते।"

14. इस समय, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अपीलकर्ता को शैक्षणिक वर्ष 2011- 2012 के लिए प्रवेश का लाभ नहीं दिया गया था क्योंकि वह नियमों के अनुसार अपने बीडीएस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने में बुरी तरह विफल रही थी और वास्तव में उसे पूरा भी नहीं किया था। एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए पूर्व-आवश्यकताएँ यह मानते हुए कि बीडीएस और एमबीबीएस पाठ्यक्रम पहले छह महीनों के लिए समान हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यद्यपि न्यायालय ने चालू वर्ष के लिए प्रवेश का लाभ नहीं दिया, लेकिन उसे अगले शैक्षणिक वर्ष में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश का निर्देश दिया क्योंकि यह एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच गया था कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश से न केवल दुर्भाग्यपूर्ण बल्कि स्पष्ट रूप से अनुचित इनकार किया गया था।

15. अनीश डी. लवांडे एवं अन्य बनाम गोवा राज्य और अन्य (2014) 1 एससीसी 554), में दो- न्यायाधीशों की पीठ एक दुखद परिदृश्य से निपट रही थी जिसमें गोवा राज्य और उसके पदाधिकारियों ने औचित्य को ताक पर रखकर प्रणालीगत अराजकता के प्रवेश की अनुमति दी थी। न्यायालय ने तीन- न्यायाधीशों की पीठ का हवाला दिया एमबीबीएस/बीडीएस चयन बोर्ड बनाम चंदन मिश्रा (1995 सप्लीमेंट (3) एससीसी 77) मामले में न्यायालय ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का प्रबंधन करने वाले प्राधिकारियों की असंवेदनशीलता पर टिप्पणी की थी और अनुमोदनपूर्वक पुन: प्रस्तुत किया था। चंदन मिश्रा बनाम एमबीबीएस/ बीडीएस चयन समिति (1994) 77 कट एलटी 624) के फैसले का वाक्य, जिसने बेहद पीड़ा में घोषणा की, "ओथेलो में शेक्सपियर ने लिखा है, "अराजकता फिर से आ गई है"। अनीश के मामले में संदर्भ गोवा के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश था। यह बताना आवश्यक है कि हालांकि तथ्यात्मक स्कोर अलग था, फिर भी दो- न्यायाधीशों की खंडपीठ ने जारी पीड़ा की गाथा को बढ़ाने के लिए आशा (सुप्रा) के फैसले का उल्लेख किया। न्यायालय ने विभिन्न अनियमितताओं और व्यक्त किए गए दृष्टिकोण पर भी उच्च न्यायालय द्वारा गौर किया। न्यायालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, यूटी चंडीगढ़ बनाम कुलदीप सिंह (1997) 9 एससीसी 199) मामले में प्राधिकरण का हवाला दिया, जिसमें न्यायालय ने जूलियस बनाम लॉर्ड बिशप ऑफ ऑक्सफोर्ड (1880) 5 एसी 214) मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में Farl Cairns L.C. की टिप्पणियों को दोहराया है, जिसे उद्धृत किया गया था। पुलिस आयुक्त बनाम गोरधनदास भानजी (एआईआर 1952 एससी 16) में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदन। संक्षेप में कहा गया अंश इस प्रकार है:-

> "27.....जिस चीज को करने का अधिकार दिया गया है उसकी प्रकृति में कुछ हो सकता है, जिस उद्देश्य के लिए यह किया जाना है उसमें

कुछ हो सकता है, उन परिस्थितियों में कुछ हो सकता है जिनके तहत यह किया जाना है, कुछ हो सकता है उस व्यक्ति या व्यक्तियों का शीर्षक जिसके लाभ के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाना है, जो शक्ति को कर्तव्य के साथ जोड़ सकता है, और उस व्यक्ति का कर्तव्य बनाता है जिसमें शक्ति निहित है, जब ऐसा करने के लिए कहा जाता है तो वह उस शक्ति का प्रयोग करता है।"

16. और उसके बाद न्यायालय यह देखने के लिए आगे बढ़ा कि राज्य सरकार ने वास्तव में उन उम्मीदवारों के भाग्य को क्रूस पर चढ़ा दिया है जिन्हें इस न्यायालय के फैसले द्वारा संरक्षित किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्पष्ट करने के बाद, न्यायालय ने व्यक्त किया:-

"26. पीड़ा और शोक यहीं समाप्त नहीं होता है। हमारी राय में, नियमों के आधार पर प्रवेश पाने वाले छात्रों की पीड़ा को संबोधित किया जाना चाहिए। सच है, उन्होंने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बजाय अदालत का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय के दरवाजे, चिंता में हो सकते हैं, क्योंकि एनईईटी परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग शुरू हो गई थी। उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर उन्हें अस्थायी प्रवेश मिल गया। उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखी है। यदि एनईईटी की शुरुआत नहीं हुई होती तो उन्हें नियमों के तहत प्रवेश दिया गया होता। लेकिन, वर्तमान में स्थिति बिल्कुल अलग है. समस्या का समाधान करने के इरादे से हमने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था।"

17. के.एस. भोईर बनाम महाराष्ट्र राज्य (2001) 10 एससीसी 264); फ़ैज़ा चौधरी बनाम जम्मू- कश्मीर राज्य (2012) 10 एससीसी 149), सत्यब्रत साहू बनाम उड़ीसा राज्य (2012) 8 एससीसी 203) और मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया बनाम कर्नाटक राज्य (1998) 6 एससीसी 131) में फैसलों का जिक्र करने के बाद, न्यायालय ने दो सिद्धांतों को खारिज कर दिया। वे हैं:-

"30. उपरोक्त निर्णयों से दो सिद्धांत उभर कर सामने आते हैं:

(i) सीटों की वृद्धि के लिए कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता, और

(ii) एक वर्ष की खाली सीटों की अगले वर्षों की अनुमत सीटों के साथ टेलीस्कोपिंग नहीं की जा सकती।"

18. न्यायालय ने प्रिया गुप्ता बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2012) 7 एससीसी 433) में प्राधिकरण का उल्लेख किया जिसमें अपीलकर्ताओं को पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति देते हुए निर्देश जारी किए गए थे और उसके बाद, न्यायालय ने निर्देश जारी करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया ताकि वह कार्य कर सके। कम से कम कुछ छात्रों के लिए एक उपशामक के रूप में जिन्हें नियमों के तहत प्रवेश दिया गया था। अंततः यह आयोजित हुआ:-

"33. हमें राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिंह और निजी उत्तरदाताओं की विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री इंदु मल्होत्रा ने सूचित किया है कि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय कोटा की 21 सीटें और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में 7 सीटें हैं। राज्य कोटे में स्थानांतरित कर दिया गया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के विद्वान वकील श्री अमित कुमार, संख्याओं पर विवाद नहीं करते हुए, प्रस्तुत करेंगे कि उन्हें विभिन्न मापदंडों पर भरा जाना है। हम

उक्त स्थिति के प्रति पूरी तरह से सचेत हैं। हालाँकि मामले की विशेष विशेषताओं और सामने आए मुकदमों और राज्य सरकार द्वारा की गई गलती को ध्यान में रखते हुए, हम यह निर्देश देना चाहते हैं कि राज्य कोटे में स्थानांतरित की गई 21 सीटें उन छात्रों में से भरी जाएंगी जो 2004 के नियमों के तहत प्रवेश लिया था। यह बताने के लिए विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि प्रवेश और स्ट्रीम का आवंटन नियमों के अनुसार उनकी परस्पर योग्यता पर होगा। हम यह स्पष्ट करने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि इनमें से किसी भी उम्मीदवार को उन स्ट्रीमों का अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो पहले से ही उन याचिकाकर्ताओं को आवंटित की गई हैं जिन्हें एनईईटी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद प्रवेश दिया गया था। बार में हमें यह भी बताया गया कि कुछ सीटें खाली हैं क्योंकि कुछ छात्रों ने कॉलेज छोड़ दिया है। यदि रिक्तियां हो गई हैं, तो उन्हें नियमों के तहत निर्धारित योग्यता के आधार पर भी भरा जा सकता है।

XXX XXX XXX

35. अगला निवेदन इस मुद्दे से संबंधित है कि क्या जिन छात्रों को इस वर्ष के राज्य कोटा में स्थानांतरित अखिल भारतीय कोटा की सीटों पर समायोजित नहीं किया जा सकता है, उन्हें अगले वर्ष समायोजित किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान हालांकि शैक्षणिक वर्ष 2014-15 में ऐसे छात्रों को प्रवेश देने के संबंध में कुछ बहस हुई, लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के विद्वान वकील श्री अमित

कुमार ने इसका गंभीरता से विरोध किया और उसके बाद, उन प्राधिकारियों का हवाला दिया गया है जिनका हमने यहां पहले उल्लेख किया है। हम उक्त उदाहरणों से बंधे हैं। कुछ व्यक्तिगत मामलों में जहां दोषपूर्ण परामर्श है और योग्यता प्रभावित हुई है, इस न्यायालय ने अगले शैक्षणिक सत्र में समायोजन का निर्देश दिया है, लेकिन मौजूदा मामले में, यह बिल्कुल सच नहीं है। यद्यपि हम कष्ट में हैं, फिर भी हमें यह व्यक्त करना चाहिए कि अगले शैक्षणिक वर्ष के संबंध में उन्हें समायोजित करने के लिए निर्देश जारी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसका सहारा लेने से अन्य मेधावी उम्मीदवार प्रभावित होंगे जो अगले प्रवेश पाने के इच्छुक होंगे। वर्ष, प्रेसेन्ती में कुछ लोगों के साथ समानता करने के लिए हम भविष्य में दूसरों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। इसलिए, प्रस्तुतीकरण निरस्त किया जाता है।" [महत्व जोड़ें]

19. उपरोक्त निर्णय को उचित रूप से समझना होगा। फ़ैज़ा चौधरी और सत्यब्रत साहू (सुप्रा) में बताए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने उन छात्रों की संख्या के समायोजन का निर्देश नहीं दिया, जिन्हें अगले वर्ष समायोजित करने के लिए बाहर जाना था, क्योंकि तथ्यात्मक स्कोर काफी अलग था। इसे विस्तृत तरीके से बताने की जरूरत है. गोवा राज्य ने नियमों का एक सेट तैयार किया था, अर्थात्, गोवा (स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नियम गोवा विश्वविद्यालय और गोवा मेडिकल कॉलेज के नियम, 2004 (संक्षेप में "नियम"), नियम 3 पात्रता, वरीयता और योग्यता क्रम से संबंधित है। नियम 3(1) पात्रता मानदंड और नियम 3(2) वरीयता से संबंधित है। उक्त नियम एकल मेडिकल कॉलेज और एकमात्र डेंटल कॉलेज, दोनों गोवा विश्वविद्यालय से संबद्ध सरकारी कॉलेजों में प्रवेश को

नियंत्रित करता है। 9.8.2012 को सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में गोवा सरकार ने अपने अवर सचिव (स्वास्थ्य) के माध्यम से शैक्षणिक वर्ष 2013- 14 के लिए एनईईटी पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की अधिसूचना को लागू करने के लिए डीन, गोवा मेडिकल कॉलेज को सूचित किया था, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बनाम पंजाब राज्य (2010) 12 एससीसी 167) में चुनौती दी गई। मामले के लंबित रहने के दौरान, रिट याचिकाकर्ताओं ने एनईईटी के लिए अर्हता प्राप्त की और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रैंक हासिल की। जब मामला इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था, तो गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2013 की रिट याचिका संख्या 366 पर विचार किया, जो एनईईटी परीक्षा में उत्तीर्ण होने में असफल रहे थे, लेकिन अपने कुल अंकों के आधार पर प्रवेश पाने के पात्र थे। नियमों के तहत दिए गए अंक, और दोनों श्रेणियों के छात्रों के संबंध में परामर्श देने और छात्रों को प्रवेश की अनुमति देने का आदेश दिया। 25.7.2013 को अतिरिक्त सचिव (स्वास्थ्य) ने गोवा मेडिकल कॉलेज को कुल अंकों के आधार पर छात्रों को प्रवेश देने का निर्देश दिया और एनईईटी के आधार पर प्रवेश रद्द कर दिया। जो उम्मीदवार एनईईटी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे और उन्हें प्रवेश मिल गया था, उन्हें कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और जो छात्र नियमों के तहत उत्तीर्ण हुए थे, उन्हें प्रवेश दिया गया। असंतोष ने दुखी छात्रों को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया और न्यायालय ने 30.7.2013 को राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी और उसके बाद 7.8.2013 को इस आशय का एक अनिवार्य आदेश पारित किया कि याचिकाकर्ताओं को अनुमति दी जाएगी। अपनी पढ़ाई जारी रखें। हालाँकि, न्यायालय ने पाया कि कुछ व्यक्तिगत मामलों में, दोषपूर्ण परामर्श दिया गया था और योग्यता हताहत हो गई थी, और तदनुसार अगले शैक्षणिक सत्र में समायोजन के लिए निर्देश दिया गया था, जो प्रिया गुप्ता (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांत का पालन करता था।

20. जैस्मीन कौर और अन्य में (सुप्रा), दो- न्यायाधीशों की पीठ ने क्षेत्र के सभी प्राधिकारियों को संदर्भित किया, अर्थात्, प्रिया गुप्ता (सुप्रा), बिहार राज्य बनाम संजय कुमार सिन्हा (1990) 4 एससीसी 624) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम मधु सिंह (2002) 7 एससीसी 258, जीएसएफ मेडिकल और पैरामेडिकल एसोसिएशन बनाम एसोसिएशन बनाम एसोसिएशन का स्व- वित्तपोषित तकनीकी संस्थान; (2003) 12 एससीसी 414) और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (सुप्रा) और आशा के मामले में निर्णय को इस प्रकार बताते हुए अलग किया:-

> "31. आशा मामले के पैरा 32 में, जिन असाधारण परिस्थितियों की जांच की जा सकती है, उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए उद्धृत किया गया है कि जब सामान्य नियम से कोई विचलन किया जाना है, तो ऐसे समान सिद्धांतों को न्यायालयों द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। पैरा 32 में, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि दुर्लभतम मामलों या असाधारण परिस्थितियों में, न्यायालयों को राहतें देनी पड़ सकती हैं और 30 सितंबर की कट- ऑफ तारीख को अपवाद बनाना पड़ सकता है, लेकिन उन मामलों में न्यायालय को पहले एक निष्कर्ष देना होगा कि उम्मीदवार की कोई गलती नहीं थी, कि उम्मीदवार ने बिना किसी देरी के अपने अधिकारों और कानूनी उपायों का तेजी से पालन किया और अधिकारियों की ओर से गलती थी और इस प्रक्रिया में नियमों, विनियमों और सिद्धांतों का कोई स्पष्ट उल्लंघन नहीं हुआ था। प्रवेश का चयन और अनुदान। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि जहां प्रवेश से इनकार करने से उम्मीदवार के समानता और समान व्यवहार के अधिकार का उल्लंघन होगा, उम्मीदवार को ऐसी असाधारण राहत से इनकार करना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और अनुचित होगा। निर्णय

के उक्त भाग पर भरोसा करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी का मामला पूरी तरह से एक असाधारण मामले के सिद्धांत द्वारा कवर किया गया था और इसलिए, डिवीजन बेंच का निर्देश अच्छी तरह से उचित था।"

21. न्यायालय ने द्वारका नाथ बनाम आईटीओ (एआईआर 1966 एससी 81) और पंजाब राज्य बनाम सलिल सभलोक (2003) 5 एससीसी 1) में निर्णयों को अलग किया और इस प्रकार निष्कर्ष निकाला:-

"33.1 व्यावसायिक कॉलेजों में प्रवेश से संबंधित कार्यक्रम का सख्ती से और ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अदालतों या बोर्ड द्वारा विचलन नहीं किया जाना चाहिए और मध्यधारा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

33.2 असाधारण परिस्थितियों में, यदि अदालत को पता चलता है कि उम्मीदवार के कारण कोई गलती नहीं है, यानी, उम्मीदवार ने बिना किसी देरी के अपने कानूनी अधिकार का तेजी से पालन किया है और केवल अधिकारियों या वहां के अधिकारियों की ओर से गलती है। यह प्रवेश देने की प्रक्रिया में नियमों और विनियमों के साथ- साथ संबंधित सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है जो प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों के समानता और समान व्यवहार के अधिकार का उल्लंघन करेगा और प्रवेश की राहत निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्देशित की जा सकती है, यह होगा केवल ऐसी परिस्थिति में उम्मीदवार को असाधारण राहत प्रदान करने के लिए पूरी तरह से न्यायसंगत और निष्पक्ष रहें।

33.3 यदि संस्थानों/प्राधिकरणों की गलती के कारण किसी विशेष शैक्षणिक वर्ष के दौरान किसी अभ्यर्थी का चयन नहीं हो पाता है और इस प्रक्रिया में यदि सीटें भर जाती हैं और समय- सारिणी समाप्त होने के कारण प्रवेश देने की गुंजाइश खत्म हो जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में उम्मीदवार को उसकी किसी भी गलती के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए और यदि कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई के लिए न्यायालय उचित मुआवजा देने पर विचार कर सकता है।

33.4. जब कोई उम्मीदवार अपने गैर- चयन के खिलाफ अपने अधिकारों या कानूनी उपायों का शीघ्रता और शीघ्रता से प्रयोग नहीं करता है, तो न्यायालय प्रवेश सुरक्षित करने के रूप में उम्मीदवार को कोई राहत नहीं दे सकता है।

33.5 यदि उम्मीदवार खुद को चयन प्रक्रिया के अधीन करके और अपने गैर- चयन को जानने के बाद परिकलित जोखिम/मौका लेता है, तो वह बाद में पलट कर यह तर्क नहीं दे सकता है कि चयन की प्रक्रिया अनुचित थी। 33.6 यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार तुरंत न्यायालय के समक्ष राहत का दावा करने के अपने अधिकार को स्वीकार कर लेता है या छोड़ देता है, तो ऐसे मामलों में, कानूनी कहावत विजिलेंटिबस एट नॉन डॉर्मिएंटिबस जुरा सबवेनिअंट, जिसका अर्थ है कि इक्विटी केवल सतर्क लोगों की सहायता करती है, उनकी नहीं जो अपने अधिकारों को लेकर सोते हैं, वे अत्यधिक उपयुक्त होंगे।

33.7 अगर प्रॉस्पेक्टस को तुरंत चुनौती नहीं दी गई तो प्रॉस्पेक्टस को अवैध या अमान्य घोषित किए जाने पर भी कोई राहत नहीं दी जा सकती। एक बार जब उम्मीदवार को पता चल जाता है कि वह प्रॉस्पेक्टस के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसे यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि, उसने आवेदन को प्राथमिकता देने के बाद ही इसे चुनौती देने का फैसला किया है और पात्रता के आधार पर इसे अस्वीकार कर दिया गया है।

33.8 एक वर्ष की खाली सीटों को अगले वर्ष की अनुमत सीटों के साथ टेलीस्कोपिंग नहीं किया जा सकता है, अर्थात, कितनी भी मेधावी क्यों न हों, सीटों को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उम्मीदवार प्रवेश के योग्य है। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय उम्मीदवार को कोई राहत नहीं दे सकता है, लेकिन यह उम्मीदवार पर निर्भर है कि वह अगले शैक्षणिक वर्ष में फिर से आवेदन करे।

33.9 सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए किसी भी समय न्यायालय या बोर्ड द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है, जो विशेष रूप से भारतीय चिकित्सा परिषद के दायरे में है।

33.10 उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक सिद्धांत को प्रत्येक मामले के अद्वितीय और विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर लागू किया जाना चाहिए और किसी भी दो मामलों को समान नहीं माना जा सकता है।" [रेखांकित करना हमारा है]

22. उपरोक्त प्राधिकारी, जैसा कि रेखांकित भाग से पता चलता है, प्रवेश की राहत देने पर प्रतिबंध लगाता है, यदि यह निर्धारित समय- सीमा के भीतर है, और

फिर सीटें भर जाने पर और प्रवेश देने की गुंजाइश खत्म हो जाने पर निर्धारित करता है। समय- सारिणी का ग्रहण, तो ऐसी परिस्थितियों में, उम्मीदवार को होने वाले नुकसान, यदि कोई हो, की भरपाई के लिए उचित मुआवजा दिया जा सकता है। एस. निहार अहमद बनाम डीन वेलाम्मल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड अन्य (2016) 1 एससीसी 662) में उक्त प्राधिकार का पालन किया गया है।

23. इस संदर्भ में, हर्षाली पुत्री सुदामराव वानखेड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2005) 13 एससीसी 464) मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनाए गए फैसले का संदर्भ। उपयुक्त होगा. उक्त मामले में, अपीलकर्ता को प्रवेश परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने के बावजूद शैक्षणिक वर्ष 2004-05 में एमबीबीएस प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जिसने अपीलकर्ता को प्रवेश देने के निर्देश के आधार पर रिट याचिका खारिज कर दी थी। मधु सिंह (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर कट- ऑफ तिथि, यानी 30 सितंबर 2004 के बाद जारी नहीं किया जा सका। न्यायालय ने अपीलकर्ता की योग्यता के संबंध में उसके रुख को स्वीकार किया और निम्नानुसार निर्देश दिया: -

> "6. कॉलेज के विद्वान वकील का कहना है कि अपीलकर्ता को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2005- 2006 में कॉलेज के स्वीकृत प्रवेश में से प्रवेश दिया जा सकता है। विद्वान वकील का यह भी कहना है कि अपीलकर्ता को केवल उस शुल्क का भुगतान करना होगा जो था यदि शैक्षणिक वर्ष 2004- 2005 में सरकारी कोटा सीट के विरुद्ध प्रवेश दिया गया हो तो भुगतान करना आवश्यक है। इसके अलावा, यह कहा गया है कि अपीलकर्ता द्वारा पिछले वर्ष या इस वर्ष के लिए डेंटल

पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए जो भी शुल्क का भुगतान किया गया है, एमबीबीएस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए उसके द्वारा शुल्क के भुगतान की गणना करते समय उचित समायोजन किया जाएगा। वर्तमान शैक्षणिक 2005- 2006 वर्ष।

7. जिस प्रश्न की अभी भी जांच की जानी है, जिसकी जांच बाद में की जाएगी, वह अपीलकर्ता के करियर के एक वर्ष के नुकसान के बारे में भी होगा। उपरोक्त के मद्देनजर, हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता को 30.09.2005 तक एमबीबीएस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जाए।"

24. उपरोक्त दो अनुच्छेदों से न्यायालय की चिंता स्पष्ट है। जैसा कि हम अनुपात को समझते हैं, तीन- न्यायाधीशों की पीठ प्रवेश न देने और छात्र के करियर के एक वर्ष के नुकसान से चिंतित थी।

25. विद्वान वकील श्री परमेश्वर ने हमारा ध्यान पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ के प्रिंसिपल बनाम संजय गुलाटी और अन्य (1983) 3 एससीसी 517) के मामले में तीन जजों की बेंच के फैसले के एक अंश की ओर आकर्षित किया है। उक्त अनुच्छेद इस प्रकार है:-

"इस तरह के मामले जिनमें शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को दिया गया प्रवेश रद्द कर दिया जाता है, एक संवेदनशील मानवीय मुद्दा उठाते हैं। यह निर्विवाद रूप से सच है कि जिन अधिकारियों पर शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को प्रवेश देने का कर्तव्य है, उन्हें निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। यदि इनमें प्रवेश होता है संस्थान अनावश्यक विचारों पर बनाए जाते हैं और अधिकारी नियमों और

विनियमों द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करते हैं, उन दुर्भाग्यपूर्ण युवा छात्रों के मन में आक्रोश और निराशा की भावना पैदा होती है जो गलत तरीके से या जानबूझकर बाहर कर दिए जाते हैं। शैक्षिक में अनुशासनहीनता प्रशासकों और शिक्षकों की ओर से नैतिक मूल्यों की भावना की कमी से संस्थान पूरी तरह से असंबद्ध नहीं हैं। लेकिन इन मामलों में अदालतों को जिस समस्या का सामना करना पड़ता है, वह यह है कि यह छह महीने या एक वर्ष की अवधि तक नहीं है। दाखिले होने के बाद अदालत का हस्तक्षेप सामने आता है। ऐसे दाखिलों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को आम तौर पर उच्च न्यायालयों द्वारा यथासंभव शीघ्रता से लिया जाता है, लेकिन फिर भी, जिन छात्रों को गलत तरीके से प्रवेश दिया जाता है, वे एक या दो सेमेस्टर पूरा कर लेते हैं। निश्चित रूप से उच्च के निर्णय के समय तक कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस न्यायालय में आगे की अपील में अभी भी अधिक समय लगता है, जिससे गलत तरीके से प्रवेश पाने वाले और अन्यायपूर्ण तरीके से बाहर किए गए छात्रों के बीच समानता को समायोजित करने में और भी कठिनाइयां पैदा होती हैं। अनिवार्य रूप से, न्यायालय को वास्तविक कानूनी स्थिति की अकादमिक घोषणा से ही संतुष्ट रहना होगा। जिन छात्रों को गलत तरीके से प्रवेश दिया गया है, उन्हें इच्छुक व्यक्तियों द्वारा उनकी ओर से की गई हेराफेरी, यदि कोई हो, का परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। इसका वस्तुतः यह अर्थ हो गया है कि व्यक्ति को उचित या अनुचित तरीके से किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करना चाहिए: एक बार जब आप अंदर आ गए, तो कोई भी आपको बाहर नहीं

निकालेगा। कानून की देरी ऐसे विविध तरीकों से अपना चमत्कार दिखाती है।" [महत्व जोड़ें]

26. जैसा कि देखा गया है, सभी प्रवेशों के मामलों में योग्यता पर हमेशा जोर दिया गया है क्योंकि मेधावी छात्रों को संस्थान या उससे जुड़े व्यक्तियों की किसी गलती के कारण प्रवेश पाने में किसी बाधा का सामना नहीं करना चाहिए। उसके पास अपनी शिकायतों के निवारण के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। यह एक शिकायत है जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। यह याद रखना होगा कि किसी व्यक्ति को अधिकार कानून के शासन द्वारा प्रदान किया जाता है और यदि वह कानून का शासन स्थापित करने की प्रक्रिया के माध्यम से उपचार चाहता है और उसे इससे वंचित कर दिया जाता है, तो यह कभी भी वास्तविक न्याय के उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा। जब इस प्रकृति का कोई मामला संवैधानिक अदालत में आता है, तो यह अदालत का कर्तव्य बन जाता है कि वह यह पता करे कि क्या प्राधिकारी ने उसे प्रदत्त शक्तियों के भीतर कार्य किया था या उससे भटक गया था, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है। मौलिक अधिकार का निवारण, यदि कोई पाने का हकदार है, तो उसे केवल मुआवजा देने के संदर्भ में नहीं तौला जा सकता है। मुआवज़ा देना एक अतिरिक्त राहत हो सकती है। इसे एकमात्र उपाय के रूप में मुआवजा देने तक ही सीमित रखने से उन मौलिक अधिकारों का मूल उद्देश्य विफल हो जाएगा जिन्हें संविधान ने प्रदान किया है ताकि उक्त अधिकार कायम रहें। अधिकार को मान्यता देना, यह निष्कर्ष दर्ज करना कि अधिकार का उल्लंघन हुआ है और अपेक्षित राहत से इनकार करना अनुचित होगा। एक युवा छात्र को यह महसूस नहीं करना चाहिए कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने का उसका पूरा प्रयास कुछ अधिकारियों की गलती या नाटकीय डिजाइन के कारण निरर्थक हो जाता है और वे मुआवजे के रूप में कुछ राशि देकर बच सकते हैं। यह न केवल पीड़ादायक हो सकता है, बल्कि

अधिकारियों की ढिलाई या बुरे इरादे या लाइलाज लालच के कारण प्रीमियम देना भी हो सकता है। हम यह सोचने को तैयार हूं, ऐसी स्थिति में न्याय और भी दूर हो सकता है। संवैधानिक न्यायालय के दरवाज़े पर दस्तक देना, एक मूर्खतापूर्ण प्रयास, निरर्थकता का एक अभ्यास। यह सर्वविदित है कि कानून का इरादा कुछ भी असंभव नहीं है; "लेक्स नॉन इंटेंडिट एलिक्विड इम्पॉसिबल"। लेकिन जब यह संभावना के दायरे में हो, और राहत से इनकार करने से "न्याय की महिमा" को ठेस पहुंचती हो, तो इसे नकारा नहीं जाना चाहिए। इसके विपरीत, राहत देने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। कहने की जरूरत नहीं है, राहत पाने के लिए, पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करना होगा, और यही आशा (सुप्रा) और हर्षाली (सुप्रा) में सटीक रूप से कहा गया है।

27. इस संदर्भ में, अदालत के विद्वान मित्र श्री नरसिम्हा ने प्रस्तुत किया कि जैस्मीन कौर (सुप्रा) में अदालत को संवैधानिक अपकृत्य के मामलों में इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए सिद्धांत द्वारा निर्देशित किया गया है। उन्होंने हमारा ध्यान रुदुल शाह बनाम स्टेट ऑफ़ बिहार (1983)4 एससीसी 141) मामले में अधिकारियों की ओर आकर्षित किया है। सेबेस्टियन होंग्रे बनाम भारत संघ (एआईआर 1984 एससी 571) और अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड बनाम चंद्रिमा दास (2000) 2 एससीसी 465), जहां न्यायालय ने मुआवजा दिया क्योंकि कोई अन्य विकल्प नहीं था और मोचन का एकमात्र तरीका मुआवजा देना था। यह बताना जरूरी है कि कानूनी रूप से देय राहत देना अदालत का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। जहां पुनर्स्थापन का सिद्धांत लागू किया जा सकता है और वहां कोई असंभवता नहीं है, उसे अस्वीकार करना न्याय के लिए अभिशाप होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि एक अवधारणा के रूप में पुनर्स्थापन की सराहना की जाती है, जैसा कि परंपरागत रूप से समझा जाता है, एक पीड़ित पक्ष की गलत काम करने से पहले की स्थिति में बहाली है। इसे केवल मौद्रिक परिमाणीकरण तक ही सीमित किया जा सकता है। यदि उल्लंघन का समाधान करने में सक्षम नहीं है। ऐसा होने पर, गलत

तरीके से प्रवेश से वंचित करने के लिए मुआवजा पर्याप्त या एकमात्र उपाय नहीं हो सकता है, क्योंकि यह किसी छात्र के शैक्षणिक करियर को प्रभावित करता है। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां क्षतिपूर्ति बहुत कठोर हो सकती है। फिर, जैसा कि हम सोचते हैं, यथोचित रूप से दूरबीन बनाना असंभव नहीं है। अनीश डी. लवांडे (सुप्रा) में कुछ उम्मीदवारों को समायोजित किया गया था क्योंकि सरकार ने पोसम खेला था और टेलीस्कोपिंग की अनुमति नहीं थी क्योंकि उम्मीदवार इस न्यायालय के फैसले के उल्लंघन में पाठ्यक्रम में शामिल हो गए थे। तथ्यात्मक स्कोर अलग था. लेकिन जब किसी अधिकार को दुर्भावनापूर्ण डिज़ाइन द्वारा कमज़ोर कर दिया जाता है, तो हम सोचते हैं, वर्तमान में पीड़ित व्यक्ति का अधिकार मायने रखना चाहिए, न कि भविष्य के उम्मीदवार का अधिकार। वर्तमान को वर्तमान के बदले सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता। चाहे जो लाभार्थी अंदर आ गया है उसे बाहर जाना चाहिए या नहीं, यह इस न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा।

28. इस संबंध में, हम लाभ के साथ, जंग सिंह बनाम बृज लाल और अन्य (एआईआर 1966 एससी 1631) में निर्धारित आदेश का उल्लेख कर सकते हैं। उक्त मामले में, न्यायालय ने सिद्धांत एक्टस क्यूरिया नेमिनेम ग्रेवबिट लागू किया, अर्थात्, न्यायालय का कोई भी कार्य किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा और उस संदर्भ में कहा गया:-

> "इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक वादी को सतर्क रहना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन जहां एक वादी अदालत में जाता है और अदालत से सहायता मांगता है ताकि डिक्री के तहत उसके दायित्वों को उसके द्वारा सख्ती से पूरा किया जा सके, यह न्यायालय पर निर्भर है, यदि यह वादी को उसके अपने उपकरणों पर नहीं छोड़ता

है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि सही जानकारी प्रस्तुत की गई है। यदि न्यायालय जानकारी प्रदान करने में कोई गलती करता है, तो वादी की जिम्मेदारी, हालांकि यह पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है, कम से कम साझा की जाती है न्यायालय। यदि वादी उस जानकारी के आधार पर कार्य करता है तो न्यायालय उसे उस गलती के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता जो उसने स्वयं की है। न्यायालय के मार्गदर्शन के लिए इससे बढ़कर कोई सिद्धांत नहीं है कि न्यायालय के किसी भी कार्य से वादी को नुकसान न पहुंचे। और यह देखना न्यायालयों का परम कर्तव्य है कि यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय की गलती से नुकसान होता है तो उसे उस पद पर बहाल किया जाना चाहिए जिस पर वह उस गलती के लिए होता। इसे इस कहावत में उपयुक्त रूप से संक्षेपित किया गया है: "Actus curiae neminem gravabit."

29. और उसके बाद राहत को ढाला, इस प्रकार देखते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया:-

"न्यायालय द्वारा की गई गलती को ठीक किया जाना चाहिए। मामले को उस स्तर पर वापस जाना चाहिए जब अदालत द्वारा गलती की गई थी और अपीलकर्ता को भोला सिंह को भुगतान के लिए अतिरिक्त रुपये जमा करने का आदेश दिया जाना चाहिए। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है हमारे द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर जमा करने पर उसका मुकदमा खारिज किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं। हालांकि, हम बता सकते हैं कि हम इस सवाल का फैसला नहीं

कर रहे हैं कि क्या कोई अदालत प्रीम्पशन डिक्री पारित करने के बाद मूल रूप से जमा करने के लिए निर्धारित समय को बढ़ा सकती है। वह प्रश्न यहां नहीं उठता है। न्यायालय की गलती को ध्यान में रखते हुए, जिसे सुधारने की आवश्यकता है, पार्टियों को 6 जनवरी, 1958 को जिस स्थिति पर कब्जा किया गया था, उस स्थिति में वापस कर दिया गया है, जब न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई थी, कौन सी त्रुटि की जा रही है हमारे द्वारा ननक प्रो ट्यून को ठीक किया गया" [जोर दिया गया]

30. उक्त निर्णय में जो तीन शब्द घोषित किए गए हैं, अर्थात्, ननक प्रो रनक, मूल रूप से संबंध के सिद्धांत के दायरे में हैं और इसे न्यायालय की गलती के कारण लागू किया जाता है, वादी को नुकसान नहीं उठाना चाहिए। इस समय, हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि जब अदालतें यह कहने की हद तक चली गई हैं कि अदालत की गलती के लिए वादी को कष्ट नहीं उठाना चाहिए, तो यह अकल्पनीय है कि प्रशासकों या परामर्श निकाय की गलती के लिए या किसी प्रकार के दुष्ट डिज़ाइनर के लिए मुआवज़ा देना ही एकमात्र उपाय माना जाना चाहिए। हम नहीं सोचते; जैसा कि हमें जस्टिनियन की कही गई बात याद आती है, "न्याय हर किसी को उसका हक दिलाने की निरंतर और शाश्वत इच्छा है।" अनावश्यक रूप से, "उसका देय" का अर्थ केवल "प्रैसेन्टी में कानून के अनुसार देय" हो सकता है।

31. उपरोक्त के मद्देनजर, हमें लगता है कि चंडीगढ़ प्रशासन (सुप्रा) के फैसले पर एक बड़ी बेंच द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है। उपयुक्त बड़ी पीठ के गठन के लिए कागजात भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे जाएं।

दिव्या पांडे मामला बड़ी बेंच को संदर्भित किया

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक मयंक चौधरी अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।